

दैनिक जागरण

इंजीनियरिंग कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई जल्द

रुच्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार अपने इंजीनियरिंग संस्थानों व पॉलीटेक्निक कालेजों के छात्रों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा जल्द शुरू करेगी। शिक्षकों के रिक्त पांच सी पदों को तीन माह में भर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी की जाएगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के बाद मंत्री अशुतोष टंडन ने यह दावा किया। कहा कि सरकार इंजीनियरिंग कालेजों की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए ई-साइबेरी की स्थापना होगा, जिसका लाभ निजी इंजीनियरिंग कालेज के छात्र भी ले सकेंगे। कालेजों के छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट के लिए हेजियर मेलों का आयोजन होगा। छात्रावासों का निर्माण करना जाएगा और छात्रवृत्ति वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 126 गुनकरीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में से 40 किरये के भवन में चल रहे हैं। इनमें से 10 पॉलीटेक्निक कालेजों को इसी शैक्षणिक सत्र में अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

श्रीधर पर होगा फोकस : मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों के मुताबिक इंजीनियरिंग कालेजों व तकनीकी विश्वविद्यालयों

में शोध को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। इसके लिए प्रत्येक संस्थान में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स उपलब्ध कराने जाएंगे। विश्वेश्वरीया रिसर्च प्रमोशन स्कैम शुरू होगी। और पीएचडी व एमटेक के 50-50 छात्रों को शोध छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पॉलीटेक्निक संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पत्रकार वर्ता में रुज्वमंत्री प्राविधिक शिक्षा संदीप सिंह, प्राविधिक शिक्षा के सचिव मुकेश मेश्रम व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

यह भी होगा

- निर्धारित शुल्क के साथे ज्यादा फीस वसूलने वाले संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

- विदेशी तकनीक विशेषज्ञों को वर्त कुलाकर उनके लेक्चर कराने जाएंगे और इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रों को विदेश भेजा जाएगा।

- एबीजे विश्वविद्यालय में सेन्टर फर एडवांस स्टडीज की जाएगी, जहां परस्नातक स्तरीय दो पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।

- एक साल के अंदर लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी।